

प्रेषक,

एनोएराओनपलव्याल,
प्रमुख राजिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजरव विभाग

देहरादून: दिनांक: १० मई, २००६

विषय:—मैं ३० टी०जी०लैजर एण्ड रिसोर्ट्स प्रा०लि० को होटल/रिसोर्ट्स निर्माण हेतु जनपद देहरादून की तहसील देहरादून के ग्राम तरला नांगल में कुल ०.७०७० हेक्टर भूमि क्य की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय:

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-४०६/१२ए-४८(२००५-०८)/डी०एल०आ०र०सी० दिनांक २० अप्रैल, २००६ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मैं ३० टी०जी०लैजर एण्ड रिसोर्ट्स प्रा०लि० को होटल/रिसोर्ट्स निर्माण हेतु उत्तरांचल (उ०प्र० जार्मीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०) (अनुकूलन एवं सुपान्तरण आदेश, २००१) (रांशोधन) अधिनियम, २००३ दिनांक १५.१.२००४ की धारा-१५४(४)(३)(क)(ii) के अन्तर्गत तहसील देहरादून के ग्राम तरला नांगल में कुल ०.७०७० हेक्टर भूमि क्य करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिचंद्रों के राथ प्रदान करते हैं—

- १— केता धारा-१२९-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूगिधर बना रहेगा और ऐसा भूगिधर भविष्य में केवल राज्य रारकार या जिले के कलैफ्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति रो ही भूमि क्य करने के लिये अह होगा।
- २— केता वैक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि वधक या रृष्टि विधिता कर राकेगा तथा धारा-१२९ के अन्तर्गत भूगिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लागों को भी ग्रहण कर राकेगा।

- ३— केता द्वारा क्य की भई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्य पिलैख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की


 (2)

गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे खीकृत किया गया था, उससे मिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कर्य किया गया था उससे मिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 4— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूखामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुरूपित जाति के गृहियों की स्थिति में गृहि क्षय रो पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
 - 5— जिस भूमि का संकरण प्रस्तावित है उसके भूखामी अरांकमणीय अधिकार वाले भूभिंधर न हों।
 - 6— इथापित किये जाने वाले होटल/रिसोर्ट में उत्तरांचल के लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार/रोवायोजन उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 7— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत रवीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भारतीय-

(एनोएसोनप्लच्याल)
प्रमुख राजिव।

संख्या एवं तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

आद्या-४

(सांहन लाल)

अपर सचिव ।